2 जनवरी 2013

भारत – आसियान संबंध – एक नए संवाद में प्रवेश

*डॉ. विभांशु शेखर **

भारत-आसियान संबंध 20-21 दिसम्बर, 2012 को इस साझेदारी वार्ता के बीस वर्ष और साझेदारी सम्मेलन के दस वर्ष के स्मरणीय शिखर सम्मेलन मनाने के दौरान एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। यह शिखर सम्मेलन एक आर्थिक समझौते, एक प्रभावी भारतीय-आसियान कार रैली, दोनों क्षेत्रों के बीच बहु-पक्षीय कनेक्टिविटी की प्राप्ति पर बल, एवं एक स्थायी व शांतिपूर्ण क्षेत्रीय व्यवस्था सृजित करने के लिए साथ कार्य करने हेतु विनिश्चय के साथ समाप्त हुआ। वर्ष 2004 की अपनी पथप्रवर्तक घोषणा – शांति और साझा समृद्धि के लिए भारत -आसियान साझेदारी- पर आधारित इस स्मरणीय शिखर सम्मेलन ने भारत-आसियान संबंधों में गुणात्मक वृद्धि को चिह्नित किया।

इस स्मरणीय शिखर सम्मेलन में एक दृष्टिकोण विवरण को अंगीकृत किया गया जिसने वर्ष 2004 में पहली बार इस संबंध को एक रणनीतिक साझेदारी, एक उद्देश्य जिसे स्थान प्राप्त हुआ, तक बुलंद किया जब भारत और आसियान एक 'दीर्घकालिक सहयोगात्मक साझेदारी ' को विकसित करने पर सहमत हुए। इस साझेदारी के दो महत्वपूर्ण संघटकों की पहचान की जा सकती है। पहला, इसमें भारत और आसियान के समुद्री राष्ट्रों के रूप में मुख्य चरित्र पर जोर दिया गया है और इसलिए समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा सर्वोपरि बन जाती है। 'भारत-प्रशांत' शब्द का समावेश जो स्मरणीय शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भारतीय प्रधानमंत्री के शुरूआती विवरण में दो महासागरीय प्रणाली (हिंद और प्रशांत) के समेकित क्षेत्र संकेत देता है, भारत-आसियान रणनीतिक अनुबंध की समुद्री प्रकृति की आवश्यकता की प्रतिपुष्टि करता है। दूसरा , क्षेत्रीय शांति और स्थिरता (क) भारत और आसियान के बीच रणनीतिक सहयोग , (ख) इस क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में आसियान - केन्द्रीयता, और (ग) इस क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा अवसंरचना व वर्तमान में उभरती संस्थाओं के प्रेरक बल के रूप में आसियान की भूमिका के लिए अनिवार्य है।

आज, भारत-आसियान संबंध एक नयी प्रफुल्लता और ऊर्जा से ओत -प्रोत है क्योंकि वे न केवल भारत -आसियान स्तर पर बल्कि इस पूरे क्षेत्र स्तर पर अधिक आर्थिक समाकलन की ओर बढ़ रहे हैं। सेवा और निवेश में भारत -आसियान मुक्त व्यापार समझौते के सफल परिणाम को संदर्भित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत -आसियान संबंधों को एक 'उत्साहजनक चरण' बतलाया जहांएक दशक में ही उनके द्विपक्षीय व्यापार के200 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंचने की संभावना है। भारत और आसियान ने आर्थिक सहयोग के विस्तारित फलक से आने वाली मुख्य प्रेरणा के साथ 2015 के अंत तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य का निर्धारण किया है।

इसके अतिरिक्त, भारत पैन-भारत-प्रशांत आर्थिक समाकलन हेतु समझौते की आसियान की नयी पहल का भी हिस्सा है जिसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सोलह संस्थापक सदस्य (दस आसियान देश और छह वार्ता साझेदार - आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड) शामिल हैं, जिसे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदार के रूप में जाना जाता है। आरसीईपी भारत को एक व्यापक आर्थिक समाकलन में स्थान प्रदान करेगा, यह एक ऐसा अवसर है जिसकी वह प्रतीक्षा करता रहा है, जब से उसने 1990 के दौरान एशिया- प्रशांत आर्थिक सहयोग की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी को अस्वीकार किया था।

भारत-आसियान के स्मरणीय शिखर सम्मेलन में इस बात को रेखांकित किया गया कि कोई भी अर्थपूर्ण समाकलीन और रणनीतिक साझेदारी बहु -फलकीय कनेक्टिविटी जिसमें वास्तविक , लोगों के बीच संबंध , कारोबार और संस्थाएं शामिल हैं, के बिना अरक्षणीय है। इसके अतिरिक्त, भारत-आसियान कनेक्टिविटी केवल भारतीय प्राथमिकता नहीं रह गयी है बल्कि आसियान की प्राथमिकता भी है जिसमें कतिपय आसियान देशों और तृतीय पक्षों से निवेश आने का आश्वासन मिला । भारत और आसियान नवम्बर, 2012 में नोम्पेंह में एक नए राजमार्ग- भारत-म्यांमार-लाओस-वियनाम-कंबोडिया राजमार्ग को विकसित करने तथा अत्यधिक विलंब वाले भारत -म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को लाओस

और कंबोडिया तक विस्तारित करने पर सहमत हुए। 26 दिवसीय भारत-आसियान कार रैली जिसका नई दिल्ली में 21 दिसम्बर को लगभग 8000 किमी. यात्रा और आईएनएस सुदर्शिनी की समुद्री यात्रा के बाद समापन हुआ , ने किसी भी अर्थपूर्ण समाकलन के लिए भारत -आसियान कनेक्टिविटी की अपरिहार्यता को उद्धृत किया। इसे भी ध्यान में लाया गया था कि मुक्त हवाई क्षेत्र संबंधी शीघ्र समझौते से भारत-आसियान कारोबार संबंधों को एक प्रेरणा मिलेगी।

आसियान के देशों में यह स्वीकार्यता बढ़ रही है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की जिम्मेदारी अधिक है और उसे अधिक बड़ी भूमिका अदा करनी है। इस क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता को आकार देने में नई दिल्ली की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है जो अनिश्चित्ता, बहुपक्षीयशत्रुता और बहु ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जहां मनीला और हनोई ने इस क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में नई दिल्ली की सक्रिय भागीदारी का आह्वान कियायथा दक्षिणी चीन सागर मुद्दे का समाधान, वहीं नोम्पेंह ने भारत से 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। मार्च 2011 में ट्रैक -।। स्तर पर दिल्ली वार्ता -।।। की कार्यवाही के दौरान इस रूख में और गति आयी जब मई , 2010 के बाद से दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि में विशेषज्ञों और नेताओं द्वारा इस क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका की मांग की गयी।

नई दिल्ली एक क्षेत्रीय ताकत के रूप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है। शायद, भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान (क) क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक सकारात्मक ताकत के रूप में कार्य करना , (ख) आसियान सहयोग ढ़ांचे के पीछे अपनी आर्थिक, कूटनीतिक और निर्देशात्मक ताकत पर भरोसा करना और (ग) सीएलएमवी देशों में क्षमता वर्धन में शामिल होना हो सकता है। भारत 2015 में आसियान समुदाय को महसूस करने के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग और समर्थन पर भी सहमत हुआ है।

भारत को धरातल पर अपने मूर्त कार्यों से आर्थिक अथवा रणनीतिक भूमिका के संदर्भ में अपनी नयी प्रोफाइल के अनुसार कार्य करना चाहिए और आसियान देशों की रणनीतिक अनिश्चितता व अस्थिरता की दुरावस्था को सुधारना चाहिए। नई दिल्ली के लिए समय आ गया है कि वह अपने वादों को पूरा करें और घोषित नीतियों को कार्यान्वित करें। शायद नालंदा विश्वविद्यालय तथा आसियान-भारत केन्द्र की स्थापना के शीघ्र कार्यान्वयन से समन्वित भारत -आसियान समुदाय के पहिए को गति मिल सकती है।

** डॉ विभांशु शेखर, भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं*

*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।